# मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश दिये: पाक नागरिकों के वीज़ा निरस्त करें

## केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से वार्ता में गृह मंत्रालय के निर्देशों की पूरी पालना पर जोर दिया

जयपुर, 25 अप्रेल। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता के पश्चात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान नागरिकों के वीज़ा के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों का राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी।

जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक वी.सी. के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क वीज़ा, शनिवार 26 अप्रैल से, एवं दीर्घकालिक वीज़ा, राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा को छोड़कर, सभी मौजूदा वैध वीज़ा रविवार 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए

■ **मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी जिला कलैक्टर व पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।**

इस क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने शुक्रवार को सचिवालय में सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, सी.आई.डी. सुरक्षा पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल, गृह विभाग की शासन उप सचिव सोविला माथुर, राजेश जैन, समस्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी

मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल, 2025 तक ही वैध रहेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन अटारी बॉर्डर से किया जाना है।

एसीएस (होम) ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों एवं एफ.आर.ओ को निर्देश दिए कि ऐसे पाक नागरिक, जो लाँग टर्म वीज़ा के अतिरिक्त अन्य वीज़ा पर राज्य में निवासरत हैं, उनके निष्कासन की कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में वर्णित समय सीमा के अनुसार की

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा*

जाये।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पिछले बुधवार को कानून व्यवस्था के सम्बंध में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य में पूर्ण चौकसी रखने, आमजन और पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने, सोशल मीडिया पर निगाह रखने की अक्षरशः पालना के भी निर्देश दिए गए।

## बीएसएफ जवान को छोड़ने से इन्कार कर रहे हैं पाक रेंजर्स

चंडीगढ़, 25 अप्रैल। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर गलती से सरहद लांघ कर पड़ोसी मुल्क की सीमा से पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवान को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ कांस्टेबल पीके सिंह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच दो बार फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन दोनों बार

■ **गलती से सीमा पार गया बीएसएफ का जवान 48 घंटे से पाक रेंजर्स की गिरफ्त में है। बीएसएफ तथा पाक रेंजर्स की फ्लैग मीटिंग भी हुई है पर नतीजा नहीं निकला।**

मीटिंग बेनतीजा रही। बीएसएफ अधिकारियों को पाकिस्तान की हिरासत में कांस्टेबल पीके सिंह की चिंता सता रही है। यह भी चिंता हो रही है कि पाकिस्तानी सेना बीएसएफ जवान के साथ किस तरह का सलूक कर रही होगी। 48 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले जब कभी भी गलती से कोई जवान एक-दूसरे मुल्क की सीमा में आता या जाता था तो उसे फ्लैग मीटिंग के बाद वापस लौटा दिया जाता था। कई बार तो दोनों देशों के नागरिकों को भी इसी तरह सुरक्षित लौटाया गया है।

# राजा इक़बाल दिल्ली के नए मेयर निर्वाचित

## डिप्टी मेयर के पद पर जय भगवान यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। भाजपा के राजा इक़बाल सिंह दिल्ली के मेयर और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर चुने गए।

दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के आज हुए चुनाव में राजा इक़बाल ने मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह को 125 वोटों से हराया। मेयर पद के निर्वाचन के लिए कुल 142 वोट डाले गए जिसमें से एक वोट अवैध घोषित किया गया।

राजा इक़बाल को 133 मत प्राप्त हुए वहीं मनदीप सिंह ने आठ मत हासिल किये। इससे पहले राजा इकबाल सिंह दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर भाजपा के जय भगवान यादव डिप्टी मेयर के पद पर निर्विरोध चुने गए। जय भगवान यादव बेगमपुर, वार्ड संख्या-27 से पार्षद हैं। उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, कांग्रेस की पार्षद, सुअरीबा खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

राजा इक़बाल सिंह मेयर चुने जाने के बाद कहा कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार दिल्ली के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने

■ **राजा इकबाल को 133 और उनके प्रतिद्वंदी, कांग्रेस के मनदीप सिंह को मात्र 8 वोट मिले। जय भगवान के सामने खड़ी प्रत्याशी कांग्रेस की अरीबा खान ने नाम वापस ले लिया।**

कहा कि शहर में स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं की दिशा में योजनाबद्ध रूप से सकारात्मक कार्य किये जायेंगे। कूड़े के पहाड़, जलभराव की समस्या के समाधान की तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में विकास को जो गति धीमी हो गयी थी उसको गति दी जायेगी और जनता के हित में बिना भेदभाव के जनहित में कार्य किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव का बहिष्कार किया और चुनाव में भाग नहीं लिया।

## 'भारत और पाकिस्तान संयम बरतें'

संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली, 25 अप्रैल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में बढ़ती कड़वाहट के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि स्थिति और न बिगड़े।

महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को दैनिक प्रेस वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा

■ **संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, दोनों देश यह सुनिश्चित करें कि स्थिति न बिगड़े।**

कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दोनों देशों में से किसी के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह स्थिति पर बहुत बारीकी से और बहुत चिंता के साथ नजर रख रहे हैं।

दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 21 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने में बहुत स्पष्ट है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था।

### दो दिन में ही ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

से ज्यादा लोग आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर निर्भर हैं। पहलगाम हादसे के कारण पहले ही भारी नुकसान हुआ है, बल्कि जनता में नकारात्मक छवि भी बनी है।

राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों ने डर बढ़ा दिया है, जो लोग छुट्टियों में कश्मीर आने की योजना बना रहे थे, अन्य विकल्प खोज रहे हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड आदि।

इसी बीच, छोटे-छोटे व्यवसायियों, सोनमर्ग के टट्टू वाले से लेकर श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट वालों तक, को इस नुकसान की पीड़ा महसूस होने लगी है।

लेक में हाउस बोट चलाने वाले अल्ताफ अहमद ने कहा, हम अभी ही तो महामारी के नुकसान से उबरने लगे थे। इस हमले ने हमारे भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने और पर्यटकों को आश्वासन देने के लिए त्वरित कदम उठाए। लेकिन उद्योग जगत जानता है, नुकसान खासकर मानसिक क्षति बहुत गहरी है। पर्यटकों का भरोसा बहाल होने में समय लगेगा।

कश्मीर फिर से घायल है और लोग, खासकर वे, जिनकी आजीविका पर्यटकों पर निर्भर है, वही दर्दनाक सवाल पूछ रहे हैं कि बंदूकें कब शांत होंगी और पर्यटक आना कब शुरु होंगे।

## पहलगाम आतंकी हमले के संदिग्धों के घर विस्फोट से तोड़े

श्रीनगर, 25 अप्रैल। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिलों में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकवादियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिन पर पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल होने का संदेह है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ये घर पुलवामा के त्राल के मोनाघामा इलाके के आसिफ शेख और अनंतनाग के आदिल हुसैन थोकर के थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोटक सामग्री की मौजूदगी के कारण घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात विस्फोट करके घरों को गिरा दिया गया। अधिकारी ने कहा, "दोनों स्थानों पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलीं। संभावित खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही देर बाद बड़े

■ **तलाशी में सुरक्षा बलों को इन घरों में संदिग्ध वस्तुएं मिली थीं।**

विस्फोट करके मकान को नष्ट कर दिया गया।"

त्राल के स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि शेख के घर पर विस्फोट तब किया गया, जब सुरक्षा बलों ने परिवार को वहां से निकाल लिया था।

माना जा रहा है कि जिन दो आतंकवादियों के मकान ध्वस्त किये गये, वे उस समूह का हिस्सा थे, जिसने पहलगाम के पास बैसरन मैदान में पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

पुलिस ने गुरुवार को प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर तीन हमलावरों के स्केच जारी किए।

### भारत अब...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

जिनमें इस निर्णय के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली कानूनी चुनौतियाँ भी शामिल हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इन गतिविधियों पर बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है। "पाकिस्तान नैशनल सिक्योरिटी कमेटी" ने कहा है कि "भारत द्वारा सिन्धु जल को रोकने या उसका रास्ता बदलने के किसी भी प्रयास को "युद्ध की कार्यवाही" माना जायेगा।" सन् 1960 में हुए समझौते को उसके 24 करोड़ नागरिकों की "लाइफलाइन" बताते हुये, इस्लामाबाद ने जोर देते हुये कहा कि इस समझौते को एकतरफा रुप से स्थगित नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद ने बदले की कार्यवाही की चेतावनी दी है।

### सेना प्रमुख ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

गोलीबारी हुई।

सेना प्रमुख श्रीनगर में व्यापक सुरक्षा समीक्षा भी करेंगे। उनके पहलगाम के पास बैसरन क्षेत्र का दौरा करने की भी संभावना है, जहां पर्यटकों पर हमला हुआ था। वह हमलावरों का पता लगाने के लिए मंगलवार को शुरू किए गए अभियान की समीक्षा भी करेंगे।

# केन्द्र ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

## केन्द्र सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का नियंत्रण है इसलिए इन पर अंतरिम रोक न लगाई जाए

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर इस विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से दाखिल किए गए इस हलफनामे में केंद्र ने उन दलीलों को खारिज कर दिया है कि संशोधन संविधान के तहत मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

संयुक्त सचिव शेरशा सी. सैदिक मोहिद्दीन द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया है कि संशोधनों

■ **केन्द्र सरकार ने कहा कि इन संशोधनों के तहत इस्लामी मान्यताओं व मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।**

का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्ति प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना है। यह धार्मिक स्वतंत्रता या इस्लामी अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

केंद्र सरकार ने संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों के लिए संवैधानिकता की कानूनी धारणा का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अधिनियम के प्रावधानों पर अंतरिम रोक न लगाने का आग्रह किया। केंद्र के हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कहा, यह अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आयामों जैसे रिकॉर्ड रखने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित है। यह किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों या दायित्वों में हस्तक्षेप से बचता है। केंद्र ने 'वक्फ-बाय-यूजर' की छूट पर चिंताओं को भ्रामक और निराधार बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आठ अप्रैल, 2025 तक पहले से पंजीकृत सभी मौजूदा वक्फ भूमि पूरी तरह से संरक्षित हैं।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य पंजीकरण की अवधारणा 1923 से लगातार वक्फ कानूनों के तहत अस्तित्व में है। सरकार ने जोर देकर कहा कि वक्फ पंजीकरण कोई नई आवश्यकता नहीं है, संशोधन केवल नियामक हैं। इससे धार्मिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा, यह एक स्पष्ट और अनिवार्य विधायी व्यवस्था है, जो सभी वक्फों का पंजीकरण सुनिश्चित करती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर आपत्तियों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ये निकाय प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक प्रथाओं का प्रशासन नहीं करते हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि उनकी भूमिका नियामक और सलाहकार की है।

### सुप्रीम कोर्ट ने ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

गांधी भी "आपका वफादार सेवक" जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे? क्या उन्हें (राहुल) मालूम है कि उनकी दादी ने इस स्वतंत्रता सेनानी को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदार बयान मत देने दीजिये। आप स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास-भूगोल जाने बिना इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते।"

अदालत उस याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिये एक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किये गये सम्मनों को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गांधी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था तथा कहा था कि गांधी के पास उच्च न्यायालय में आने के बजाय, को ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर की धारा 397 (रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ लोअर कोर्ट) के तहत, सत्र न्यायालय जाने का विकल्प है।

सत्र न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली थी, तथा उसे अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया था, जिसने गांधी को सम्मन जारी किये थे।

अपने आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि गांधी ने कहा है कि सावरकर एक "ब्रिटिश सर्वेन्ट" थे, जिन्हें पेन्शन मिलती थी।

### नाबालिग छात्रा ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

पड़ोसी के फोन से अभियुक्त को फोन किया था और उसके बाद से उसकी बेटी का कोई पता नहीं है। इसके अलावा, अभियुक्त को नंबर भी बंद आ रहा है। अभियुक्त उसकी बेटी को बहलाकर ले गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जांच में पता चला कि आरोपी, पीड़िता को गाजियाबाद, दिल्ली और गोवा सहित अन्य जगहों पर ले गया था और वहां पर उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया।

## ईरान और सऊदी अरब ने भारत -पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की

तेहरान, 25 अप्रैल। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दोनों ओर से हो रही आक्रामक बयानबाजी से उपजे तनाव और जंग की आशंका को देखते हुए दुनिया के दो अहम देश चीजों को ठीक करने के लिए आगे आए हैं। ये देश मुस्लिम जगत की दो बड़ी ताकतें- ईरान और सऊदी अरब हैं। ईरान ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वहीं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की पुष्टि की है।

ईरानके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार शाम एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री

■ **सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत व पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसकी पुष्टि की।**

ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ईरान के पड़ोसी हैं। दोनों ही देशों के साथ ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। ईरान पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को अपनी प्राथमिकता मानता है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में है। ईरान इस मुश्किल समय में दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने के लिए तैयार है।

सैयद अब्बास अराघची ने फारसी कवि सादी की कविता अपने ट्वीट के साथ शेयर की है। इस कविता का भाव कुछ इस तरह से है कि दुनिया के सभी इंसान एक ही तरह के हैं। अगर कहीं एक इंसान को दर्द होता है, तो बाकी इंसान भी बेचैन रहेंगे। इस कविता का मतलब यही है कि दुनिया में हर जगह शांति रहे और सभी इंसान एक दूसरे से प्यार करते हुए अमन से रहें।

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी के विदेश मंत्री से बातचीत होने की जानकारी दी है। इशाक डार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सऊदी के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई है। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के एकतरफा फैसलों के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में लिए गए निर्णयों के बारे में प्रिंस फैसल को जानकारी दी।

### इसरो के पूर्व ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कस्तूरीरंगन के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया है। उन्होंने महान वैज्ञानिक के परिवार, उनके विद्यार्थियों, वैज्ञानिक साथियों तथा अनगिनत प्रसंशकों के प्रति दुख की इस घड़ी में संवेदना व्यक्त की है।

मोदी ने कहा, नयी शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा तैयार करने में डॉ. कस्तूरीरंगन की भूमिका के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। डॉ. कस्तरीरंगन ने इस नीति में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश में पढ़ाई-लिखाई अधिक समग्र तथा भविष्योन्मुखी हो। उन्होंने अनेक वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं का विलक्षण रूप से पथ-प्रदर्शन किया।

डॉ. कस्तूरीरंगन 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के निर्माता थे।

# नेशनल हैरल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को राहत

## रॉउज़ एवेन्यु कोर्ट ने मनी लॉंडरिंग मामले में नोटिस जारी करने से इन्कार किया

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। नेशनल हैरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत को पूरा संतोष न हो जाए, तब तक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।

अदालत ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी है।

जज ने निर्देश दिया कि ईडी पहले वह दस्तावेज दाखिल करे, इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार (2 मई) को होगी।

उल्लेखनीय है कि इसी महीने ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की है।

ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए।

इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती।

आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है।

### 'हम तीन दशक से ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

उन्होंने कहा, "हम भारत द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का जवाब नाप तोल कर देंगे। अगर कोई पूर्ण हमला होता है, तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर भी पूर्ण युद्ध होगा।" उन्होंने आगे कहा, "अगर चीजें गलत दिशा में गई, तो इस टकराव का दुखद परिणाम हो सकता है।"

जब उनसे पूछा गया कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया: "हाँ, मुझे ऐसा लगता है। दो परमाणु शक्तिों के बीच टकराव हमेशा चिंता का विषय होता है।"

बिना किसी सबूत के, उन्होंने भारत पर पहलगाम हमले को "स्टेज" करने का आरोप लगाया और देश में चल रही इन अटकलों को बल दिया कि यह कदम शायद आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र केंद्र सरकार की गिरती साख को बचाने के लिए उठाया गया हो।

उन्होंने दावा किया, "हम यह समझ सकते हैं कि यह पूरी घटना किसी प्रकार के क्षेत्रीय संकट को पैदा करने के लिए रची गई थी, विशेष रूप से हमारे खिलाफ।"

जब उनसे पूछा गया कि उनका क्या मतलब है, तो आसिफ ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारी सरकार भी, पिछले दो दिनों में इस घटना की बिना शर्त कड़ी निंदा कर चुकी है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।"

जब उनसे सीधा पूछा गया कि क्या वे भारत को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आसिफ ने जवाब दिया: "हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, वे खुद ही ऐसी स्थितियां बनाते हैं।"

### पाक नागरिकों ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

इससे पहले केंदीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर उनसे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा था।

## भारत ने अपने "रैस्पाँस" से पाकिस्तान...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

अलावा, देश का विदेशी कर्ज, जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) के 40 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है, जिसे चुकाना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। भारत के हालिया कदमों ने इन आर्थिक परेशानियों को और गहरा कर दिया है।

भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला पूरे पाकिस्तान में चिंता की लहर पैदा कर रहा है। सिंधु नदी पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था की जीवन रेखा है, जो देश की जी.पी.डी. का लगभग 24 प्रतिशत है और करीब 40 प्रतिशत आबादी को रोजगार देती है। यदि भारत इस महत्वपूर्ण जल स्रोत को रोकता है, तो इससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इससे न केवल खाद्य संकट पैदा होगा, बल्कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। पहले से ही कम पैदावार और बढ़ती लागत से परेशान किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। कृषि उत्पादन में गिरावट से जी.डी.पी. में 1.5 से 2 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है, जो पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति को और बिगाड़ देगी। आम नागरिक इस प्रभाव को सबसे ज़्यादा महसूस करेगा, जब खाद्य सामग्री और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी।

इसके साथ ही, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्गों को बंद करना पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा झटका है। दोनों देशों के बीच होने वाला, सालाना 2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार ठप्प हो गया है, जिससे उन उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं, जो भारतीय सामानों पर निर्भर थीं। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर, जो पहले से ही कच्चे माल के बढ़ते दामों और महंगाई के दबाव में है, के सामने अब महंगे विकल्प तलाशने की नई समस्या भी खड़ी हो गई है।

इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी, महंगाई और ज्यादा होगी, और पाकिस्तानी उत्पाद वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा खो बैठेंगे। पहले से ही चिंताजनक व्यापार घाटा और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अब पड़ोसी देश के बाज़ारों तक उसकी पहुँच नहीं है तथा उसे दूसरे ट्रेड रुटों पर निर्भर रहना होगा, जो अधिक महंगे हैं तथा जिनमें समय भी ज्यादा लगता है।

निवेशकों का विश्वास भी गहराई से प्रभावित हुआ है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरैक्टर इन्वैस्टमैंट/एफ.डी.आई.) में और गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। 2025 की पहली तिमाही में, एफ.डी.आई. में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी और यह गिरावट जारी रहने की संभावना है, क्योंकि निवेशक अधिक सावधान हो गए हैं। सुरक्षा तथा राजनीतिक खतरों में वृद्धि के कारण, पाकिस्तान निवेशकों के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है। विदेशी पूंजी की कमी, पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर असर डाल सकती है।

इन तमाम घटनाओं का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई पहले ही बहुत अधिक है, और कृषि उत्पादन और व्यापार में अवरोध के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। खासकर ग्रामीण इलाकों में आम पाकिस्तानी परिवारों की क्रयशक्ति में भारी गिरावट आएगी। ऊर्जा क्षेत्र, जो पहले से ही संकटग्रस्त है, और अधिक चुनौतियों का सामना कर सकता है, क्योंकि जल प्रवाह कम होने से हइड्रो इलैक्ट्रिक बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। इससे बार-बार बिजली कटौती होगी, जो रोज़मर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों को और बाधित करेगी। इस परिस्थिति में व्यापक असंतोष फैलेगा, विशेषरुप से यदि जनता को ऐसा लगा कि सरकार भारत द्वारा उठाए गए कदमों के आर्थिक परिणामों से निपटने में असमर्थ है।

पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए वर्तमान स्थिति को अनदेखा करना संभव नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं, और सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सेना, जो पारंपरिक रूप से भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाती रही है, को अब अपने रुख पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। किसी भी तरह की सैन्य उग्रता के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं-विशेषकर जब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। वहीं, पाकिस्तान की सरकार को कूटनीतिक प्रयासों और देश के भीतर मजबूत प्रतिक्रिया के बीच संतुलन बनाना होगा।

**मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा,** आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:-**राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908